IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

भारत में क्रिप्टो करेंसी विनियमन: वित्तीय समावेश के अवसर और चुनौतियां

डॉ. परिपूर्णानंद तिवारी

अतिथि विद्वान - वाणिज्य संकाय

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश:

यह शोध पत्र भारत में क्रिप्टोकरेंसी (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स - VDAs) के विनियमन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है तथा वित्तीय समावेश के परिप्रेक्ष्य में इसके अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करता है। फरवरी 2026 तक भारत में कोई व्यापक क्रिप्टोकरेंसी कानून नहीं बना है। सरकार आंशिक निगरानी (PMLA के तहत FIU-IND पंजीकरण) पर जोर दे रही है, जबकि 30% फ्लैट टैक्स और 1% TDS व्यवस्था बरकरार है। RBI e-रुपया (CBDC) को बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय समावेश के लिए क्रिप्टो अंबैंकेड/अंडरबैंक्ड आबादी तक सस्ती पहुंच, रेमिटेंस और DeFi सेवाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन अस्थिरता, सुरक्षा जोखिम, नियामक अनिश्चितता और डिजिटल साक्षरता की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और संतुलित विनियमन की सिफारिश करता है ताकि लाभ अधिकतम हों और जोखिम न्यूनतम।

कीवर्ड्स: क्रिप्टोकरेंसी, विनियमन, वित्तीय समावेश, PMLA, FIU-IND, वर्चुअल डिजिटल एसेट, e-रुपया, ब्लॉकचेन, DeFi, अंबैंकेड आबादी।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

DOI: 10.48175/IJARSCT-31163